this committee that we must constitute similar committees at the divisional level also. These committees also have been constituted. We will see to it that these committees are meeting regularly and are functioning regularly. Regarding the recommendations which have been made, most of them have been implemented in the P&T department.

ग्रामीण आवास के लिए ऋण

†

*378. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री छोटूभाई पामित :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या 31 मार्च 1980 को 2.08 करोड़ मकानों की आवश्यकता थी जिसमें से गांवों में 1.61 करोड़ मकानों की कमी थी ;

(ख) क्या सरकार ने गांवों की इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना बनाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों में मकानों को बनाने के लिए ऋण देने का है; यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान कुल कितना ऋण दिया गया और आगामी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद आरिफ उस्मान) : (क) राष्ट्रीय भवन संगठन (एन० बी० ओ० के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल, 1980 को देश में 2.07 करोड़ एककों की कमी थी, इसमें से 1.61 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में थी ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण, इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य प्लानों में ग्रामीण क्षेत्रों की निम्न लिखित आवास योजनाएं शामिल हैं :–

(i) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक सिजमें काश्तकार कारीगर मछेरे आदि शामिल हैं, के लिए आवास स्थल तथा मकान बनाने के लिए सहायता की व्यवस्था करने की योजना ।

(ii) लोगों के लिए 500 - रूपये तक ऋण की व्यवस्था केलिए ग्राम आवास प्रोजेक्ट योजना ।

(ग) केन्द्रीय सरकार आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) और सामान्य बीमा निगम० (जी० आई० सी०) के माध्यम से ग्रामीणआवास के लिए राज्य सरकारों और उनके आवास अभिकरणों को ऋण दे रही है ।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान, हुडको लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण देगा, जिसमे से लगभग 16.7 करोड़ रुपये वर्ष 1980-81 के लिए है ।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के ऋणों की मात्रा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती है । केवल ग्रामीण आवास के लिए जीवन बीमा निगम से वार्षिक ऋण का मोजूदा स्तर 10 करोड़ रुपये तक है और ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास के लिए सामान्य बीमा निगम से 18 करोड़ रुपये है ।

श्री मूल चन्द डागा : सभापटल पर आप ने क्या रखा है और उसका उत्तर आप ने क्या दिया है ।

आप ने बताया है कि 2 करोड़ 7 लाख मकानों की कमी है और आप ने यह बताया है कि गांवों के अंदर 1 करोड़ 61 लाख मकानों की कमी है । आपने यह कहा है कि हम ने अब की साल 16 करोड़ रुपया राज्यों को दिया है । आप यह बताइए कि हमारे राजस्थान को कितना पैसा इस साल मिला है ।

दूसरा सवाल है . . .

MR. SPEAKER: Question Hour is over.

AN HON. MEMBER: The answer may be laid on the Table!

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Contracts Awarded Below the Prescribed and Approved Rates By C.P.W.D.

379. SHRI R.L.P. VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 'M' Division of CPWD in particular and others in general award the contracts, 40 per cent below the prescribed and approved CPWD rates;

(b) if so, whether the rates laid down are incorrect and illogical and is it because of this the quality of painting, white-washing and annual maintenance and repair works is far from satisfactory and poor; and

(c) if so, what steps are being taken by Government to safeguard the waste of public money and providing better services to the allottees of Government accommodation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHR BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Yes, Sir, the rates for painting and white-washing etc. works are being received upto 40 per cent below Delhi Scheduled of Rates, 1977.

(b) Schedule of rates are primarily meant for construction works and are quite realistic. Lower rates are received for maintenance works due to keen competition for such works. The quality of work as per the specifications prescribed in the contracts are always insisted upon.

(c) Does not arise.

Setting up of National Youth Commission

*380. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether All India Students' Leaders Conference has urged the Government for setting up National Youth Commission to look into the problems of students and to suggest remedial measures; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b). Suggestions have been received from time to time for setting up a National Youth Commission to look into the problems of students. The Government is fully seized of the problems of students and has their welfare at heart. Keeping in view the requirements of the situation and our resources, necessary action is taken by the Central Government, State Governments, Universities and other institutions of higher education for meeting the long-term problem of their welfare as also the problems that may arise from time to time. Our approach to educational development is all along sensitive to the problems as well as the needs and the overall welfare of students.

Since a number of committees and commissions, including the Education